



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2018/ज्येष्ठ 9, 1940

No. 201]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2018/JYAISTHA 9, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 मई, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/ एल. ए. डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./ 2018-15.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,
 - i. विनियम 4 में, खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:

“(घ) विदेशी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी, जो उस देश में निगमित हो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सदस्य हो और उनके कानूनी प्रावधानों के अधीन

मान्यताप्राप्त हो, और जिसका प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) की रेटिंग करने में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो;”

ii. विनियम 5 में,-

क. खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(ग) आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये की हो;”

ख. खंड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(ठ) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी के संप्रवर्तक (प्रमोटर) [विनियम 4 के अनुसार] की, साख निर्धारण एजेंसी में कम से कम 26% की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) हो।”

iii. विनियम 9 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएँगे, अर्थात्-

“(घ) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) सदैव कम से कम पच्चीस करोड़ रुपये की रहेगी:

परंतु यह कि बोर्ड के पास पहले से ही भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जिस साख निर्धारण एजेंसी की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पच्चीस करोड़ रुपये से कम हो, वह साख निर्धारण एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018 के अधिसूचित होने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपनी शुद्ध-मालियत यथा निर्धारित रकम तक बढ़ाएगी;

(ङ) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी के संप्रवर्तक (प्रमोटर) [विनियम 4 के अनुसार] की शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग), बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से कम से कम तीन वर्षों की अवधि तक, साख निर्धारण एजेंसी में कम से कम 26% की रहेगी:

परंतु यह कि यह खंड उस साख निर्धारण एजेंसी पर लागू नहीं होगा, जो बोर्ड के पास भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रारंभ के समय भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत हो;

(च) साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) या साधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) के माध्यम से प्रस्तावित प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) की रेटिंग करने से भिन्न कोई दूसरा क्रियाकलाप नहीं करेगी:

परंतु यह कि इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात किसी साख निर्धारण एजेंसी को कोई दूसरा क्रियाकलाप करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी, जहाँ तक वह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) की धारा 3(18) के अधीन यथा परिभाषित किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्युलेटर) द्वारा किया जाना अपेक्षित हो:

परंतु यह और कि यदि साख निर्धारण एजेंसी किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा अपेक्षित क्रियाकलाप से भिन्न क्रियाकलाप कर रही हो, तो ऐसा क्रियाकलाप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2018 के अधिसूचित होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर एक अलग एंटिटी को सौंप दिया जाए।”

iv. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“(1) प्रत्येक साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी, प्रतिभूतियों (जिनकी रेटिंग उसके द्वारा की गई हो) के बने रहने तक, ऐसी प्रतिभूतियों की रेटिंग का तब तक निरंतर अनुश्रवण (मॉनीटर) करती रहेगी, जब तक कि रेटिंग विनियम 16(3) के प्रावधानों (उपबंधों) के अध्यक्षीन वापस न ले ली जाए।”

v. विनियम 16 में, -

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“(1) प्रत्येक साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के बने रहने तक, समस्त प्रकाशित रेटिंगों का तब तक आवधिक पुनर्विलोकन करती रहेगी, जब तक कि रेटिंग विनियम 16(3) के प्रावधानों (उपबंधों) के अध्यक्षीन वापस न ले ली जाए।”

ख. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“(2) यदि ग्राहक साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी को इन विनियमों के विनियम 15 के अधीन उसकी बाध्यताओं का पालन करने हेतु समर्थ बनाने में सहयोग न करे, तो साख निर्धारण एजेंसी जितनी भी जानकारी उपलब्ध हो उसके आधार पर या उस प्रकार पुनर्विलोकन करेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए: परंतु यह कि यदि इस प्रकार सहयोग की कमी की वजह से रेटिंग जितनी भी जानकारी उपलब्ध हो उसके आधार पर दी गई हो, तो साख निर्धारण एजेंसी निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) को यह तथ्य प्रकट करेगी कि रेटिंग इस आधार पर दी गई है।”

ग. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात् -

“(3) साख निर्धारण एजेंसी रेटिंग तब तक वापस नहीं लेगी जब तक उस प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) के अधीन बाध्यताएँ बकाया रहें जिसकी रेटिंग उसके द्वारा की गई हो, सिवाय इसके जहाँ उस कंपनी, जिसकी प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) की रेटिंग की गई हो, का परिसमापन (वाइंड-अप) हो गया हो या उसका किसी दूसरी कंपनी में विलय (मर्जर) या समामेलन (अमैलगमेशन) हो गया हो, या जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।”

vi. विनियम 24 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

“साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) में शेयरधारिता

24क. (1) साख निर्धारण एजेंसी:

(क) प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी दूसरी साख निर्धारण एजेंसी में 10 प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता (शेयरहोल्डिंग) और / या मताधिकार नहीं रखेगी, या

(ख) का किसी दूसरी साख निर्धारण एजेंसी के बोर्ड में प्रतिनिधित्व नहीं होगा:

परंतु यह कि साख निर्धारण एजेंसी, बोर्ड के पूर्वानुमोदन (की पूर्व मंजूरी) से, किसी दूसरी साख निर्धारण एजेंसी में 10 प्रतिशत से अधिक शेयर और / या मताधिकार केवल तभी अर्जित कर सकेगी जब ऐसे अर्जन के परिणामस्वरूप उस साख निर्धारण एजेंसी के नियंत्रण में परिवर्तन हो जाता हो जिसके शेयर अर्जित किए जा रहे हों। अर्जनकर्ता (एक्वायरर) द्वारा पूर्वानुमोदन माँगे जाने के आधार पर, बोर्ड निवेशकों (विनिधानकर्ताओं) के हित और बाजार की सत्यनिष्ठा तथा स्थिरता को ध्यान में रखते हुए अर्जन (एक्विजिशन) को मंजूरी प्रदान कर सकेगा।

(2) किसी साख निर्धारण एजेंसी में 10 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर और / या मताधिकार रखने वाला शेयरधारक किसी दूसरी साख निर्धारण एजेंसी में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, 10 प्रतिशत या उससे अधिक शेयर और / या मताधिकार नहीं रखेगा:

परंतु यह कि उक्त प्रतिबंध (निर्बंधन) पेंशन निधियों, बीमा स्कीमों और पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) की स्कीमों की धारिताओं (होल्डिंग) पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “साख निर्धारण एजेंसी” (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) से बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी अभिप्रेत है।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./77/183]

पाद टिप्पण :

1. मूल विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 भारत के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7 जुलाई 1999 की का.आ. सं. 547(अ) के अधीन जारी हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तत्पश्चात्-
 - (क) 28 मार्च 2000 को का.आ. सं. 278(अ) द्वारा राजपत्र में प्रकाशित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 द्वारा
 - (ख) 29 मई 2001 को, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

- (ग) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
- (घ) 19 फरवरी 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 203(अ), द्वारा
- (ङ) 1 अक्तूबर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1160(अ), द्वारा
- (च) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- (छ) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1454(अ), द्वारा
- (ज) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा
- (झ) 19 मार्च 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2009-2010/30/199044, द्वारा
- (ञ) 13 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा
- (ट) 5 जुलाई 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/10/21232, द्वारा
- (ठ) 27 दिसम्बर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/31/39022, द्वारा
- (ड) 8 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
- (ढ) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (ण) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 (तारीख 29 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित), द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th May, 2018

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (CREDIT RATING AGENCIES)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2018**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018-15.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, namely:-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999,
 - i. in regulation 4, clause (d) shall be substituted with the following, namely: -

“(d) a foreign credit rating agency incorporated in a Financial Action Task Force (FATF) member jurisdiction and recognised under their law, having a minimum of five years’ experience in rating securities;”

- ii. in regulation 5, -

- a. clause (c) shall be substituted with the following, namely: -

“(c) the applicant has a minimum net worth of rupees twenty five crore.”

- b. after clause (k), the following clause shall be inserted, namely -

“(l) the promoter of the credit rating agency, in terms of regulation 4, has a minimum shareholding of 26% in the credit rating agency.”

- iii. in regulation 9, after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely -

“(d) the credit rating agency shall at all times maintain a minimum net worth of rupees twenty five crore.

Provided that a credit rating agency already registered with the Board under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, having a net worth less than rupees twenty five crores, shall, increase its net worth to the specified amount within a period of three years from the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2018.

- (e) the promoter of the credit rating agency, in terms of regulation 4, shall maintain a minimum shareholding of 26% in the credit rating agency for a minimum period of three years from the date of grant of registration by the Board.

Provided that this clause shall not be applicable to a credit rating agency already registered with the Board under Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, at the commencement of Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies)(Amendment) Regulations, 2018.

- (f) a credit rating agency shall not carry out any activity other than the rating of securities offered by way of public or rights issue.

Provided that nothing in these regulations shall prohibit a credit rating agency from engaging in any other activity in so far as it may be required by a financial sector regulator as defined under section 3(18) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Provided further that if a credit rating agency is carrying out activities other than the activity required by a financial sector regulator, such activity shall be segregated to a separate entity within a period of two years from the date of notification of Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies)(Amendment) Regulations, 2018.”

- iv. in regulation 15, sub-regulation (1) shall be substituted by the following, namely-
- “(1) Every credit rating agency shall, during the lifetime of securities rated by it continuously monitor the rating of such securities, unless the rating is withdrawn, subject to the provisions of regulation 16(3).”
- v. in regulation 16, -
- a. sub-regulation (1) shall be substituted by the following, namely-
- “(1) Every credit rating agency shall carry out periodic reviews of all published ratings during the lifetime of the securities, unless the rating is withdrawn, subject to the provisions of regulation 16(3).”
- b. sub-regulation (2) shall be substituted by the following, namely-
- “(2) If the client does not co-operate with the credit rating agency so as to enable the credit rating agency to comply with its obligations under regulation 15 of these regulations, the credit rating agency shall carry out the review on the basis of the best available information or in the manner as specified by the Board from time to time.
- Provided that if owing to such lack of co-operation, a rating has been based on the best available information, the credit rating agency shall disclose to the investors the fact that the rating is so based.”
- c. sub-regulation (3) shall be substituted by the following, namely-
- “(3) A credit rating agency shall not withdraw a rating so long as the obligations under the security rated by it are outstanding, except where the company whose security is rated is wound up or merged or amalgamated with another company or as may be specified by the Board from time to time”
- vi. after regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely –
- “Shareholding in a credit rating agency**
- 24A. (1) A credit rating agency shall not:
- (a) directly or indirectly, hold 10 per cent or more shareholding and/ or voting rights in any other credit rating agency, or
- (b) have representation on the Board of any other credit rating agency.
- Provided that a credit rating agency may, with the prior approval of the Board, acquire shares and/ or voting rights exceeding 10 per cent in any other credit rating agency only if such acquisition results in change in control in the credit rating agency whose shares are being acquired. On the basis of the prior approval sought by the acquirer, the Board may approve the acquisition in the interest of investors, market integrity and stability.
- (2) A shareholder holding 10 per cent or more shares and/ or voting rights in a credit rating agency shall not hold 10 per cent or more shares and/ or voting rights, directly or indirectly, in any other credit rating agency.
- Provided that the said restriction shall not apply to holdings by Pension Funds, Insurance Schemes and Mutual Fund Schemes.
- Explanation: For the purpose of this regulation, a “credit rating agency” means a credit rating agency registered with the Board.

AJAY TYAGI, CHAIRMAN

[ADVT.—III/4/Extty./77/183]

Footnotes:

1. The principal regulations, SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were issued under S.O. No. 547 (E) dated July 7, 1999 published in the Gazette of India.
2. SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 were subsequently amended on-
 - (a) March 28, 2000 by the SEBI (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 published in Official Gazette vide S.O. No. 278(E).
 - (b) May 29, 2001, by the SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) (Regulations), 2001 vide S.O. No. 476 (E).
 - (c) September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. No.1045 (E).
 - (d) February 19, 2003 by SEBI (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 203 (E).
 - (e) October 1, 2003 by the SEBI (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1160 (E).
 - (f) March 10, 2004 by SEBI (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S. O. No. 398 (E).
 - (g) September 7, 2006 by the SEBI (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2006 vide S. O. No. 1454(E).
 - (h) May 26, 2008 by SEBI (Intermediaries) Regulations, 2008 vide no. LAD/NRO/GN/2008/11/126538.
 - (i) March 19, 2010 by the SEBI (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2009-2010/30/199044.
 - (j) April 13, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/ NRO/ GN/ 2011-12/03/12650.
 - (k) July 5, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/10/21232.
 - (l) December 27, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/31/39022.
 - (m) December 08, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide Notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023.
 - (n) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification no. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089
 - (o) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037 read with notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38dated March 29, 2017.